Group Insurance Scheme for Teaching/ Non-Teaching Staff of Kendriya Vidyalaya Sangathan

2336. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the details of amount for which the Central Government teaching staff of different categories are insured under Group Insurance Scheme;

(b) what are the details of amounts for which different categories of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan are insured under this Scheme;

(c) whether there is any difference in (a) and (b) above in this regard; and

(d) if so, what are the reasons and justification therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) The Central Government employees are insured under the Group Insurance Scheme as under:

Group	Insured Amount
A	Rs. 80,000.00
B	Rs. 40,000.00
C	Rs. 20,000.00
D	Rs. 10,000.00

(b) The details of the amount for which different categories of Kendriya Vidyalaya Sangathan employees are insured is as under:

Group	Insured Amount
A	Rs. 40,000.00
B	Rs. 30,000.00
C	Rs. 20,000.00
D	Rs.10,000.00

(c) Yes, Sir.

(d) The Scheme operated in the Kendriya Vidyalaya Sangathan is a Group Saving Linked Insurance Scheme. The payment of the insured value in case of a K.V.S. teacher is made by the Life Insurance Corporation of India who are paid quarterly premium as demanded by them on the basis of the average age group of the teaching and non-teaching staff of the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The saving accounts are maintained separately in the Kendriya Vidyalaya Sangathan. The Life Insurance Corporation were not agreeable to cover the risk at par with that of Central Government employees.

नयी सड़कों का निर्माण

2337. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आटो-मोबाइल रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा पुणे में हाल ही में आयोजित एक विचार गोष्ठी में केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान के निदेशक द्वारा दिए गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तम किस्म के वाहनों की उपलब्धता के बावजूद देश में सड़कों की कमी के कारण भारत 20वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों तक गतिशीलता के लाभों से वंचित रह जायेगा ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वाहनों की सुलभ उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देश के कार्यों में गतिशीलता को बढ़ाने के लिये आगामी 3 वर्षों के दौरान नयी सड़कों के निर्माण के संबंध में कोई योजना बनायी है; और

(ग) इस प्रकार बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान के निदेशक ने

भारतीय आटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर एक सेमिनार के समापन अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में यह कहा बताते हैं कि यद्यपि देश आटोमोटिव प्रौद्योगिकी में उन्नत है लेकिन उसके लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाते क्योंकि सडकों पर अत्यधिक भीड़-भाड़ है

(ख) और (ग) सरकार को सड़कों में सुधार की आवश्यकता की जानकारी है और सीमित संसाधनों के दायरे में प्रयास कर रही है।

Expenditure Incurred on Research Work in Policy Centre of Jawaharlal Nehru University

2338. SHRI PRITHIBI MAJHI:

SHRI ARANGIL SREEDHARAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what amount is being spent annually on each student of the Policy Centre of Jawaharlal Nehru University;

(b) whether any important research work has been done in this field; and

(c) what steps have been taken to check wasteful expenditure and to ensuse that research work is conducted smoothly?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) to (c) The Centre for Studies in Science Policy in the School of Social Sciences of the Jawaharlal Nehru University was established in 1971 with the objective of developing science policy as an independent applied discipline. The Centre has awarded 10 M.Phil. and 6 Ph.D. degrees to its students, undertaken six research projects and published a number of papers. On the recommendations made by a Review Committee the Executive Council of JNU decided to suspend the Centre as an administrative unit in 1980. However, some research work continues to be undertaken by the Centre. The total expenditure incurred on the Centre since its inception is approximately Rs. 25 lakhs.

The University is making efforts to revive the Centre by recruiting suitable persons on the faculty.

दिल्ली परिवहन निगम में वित्तीय संकट के कारण

2339. श्री राम जेठमलानी :

श्री राम नरेश यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम में वित्तीय संकट के कारणों की जांच करने के लिये स्थापित की गयी विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की राय में दिल्ली परिवहन निगम में हानि के मुख्य कारण भण्डार का दुरुपयोग, कुव्यवस्थित अनुरक्षण, फजूलखर्ची अयोग्यता और भ्रष्टाचार हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या उपचारी कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इस संबंध में उठाये गये उपचारी कदमों के फलस्वरूप निगम को वर्ष-वार कितनी-कितनी बचत हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) विभिन्न अध्ययनों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के घाटों के मुख्य कारणों में अपेक्षाकृत कम भाड़ा ढांचा होना और मेजबूरी लागत सहित निवेशों की तेजी से बढ़ रही लागत है। वित्तीय निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम सतत आधार पर विभिन्न कदम उठा रहा है जिनमें कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से इनवेंटरी नियंत्रण, मितव्ययिता संबंधी उपाय करना, बेहतर